

### ❁ वैराजगारी के कारण क्या है?

स्थिति अत्यंत जंभीर है। यह विकास का भास में वैराजगारी की अस्तित्व करता है।  
 भास में वैराजगारी के कारण निम्नलिखित हैं:—

- i) सीमा आर्थिक विकास
- ii) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
- iii) कम बचत तथा निवेश
- iv) कृषि रूप में सीमा व्यस्तता
- v) लुप्त तथा लघु उद्योगों का पतन
- vi) असंयुक्त परिवार प्रणाली
- vii) नई तकनीकों का प्रयोग का अभाव
- viii) शिक्षा प्रणाली में दोष

### \* वैराजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम :-

- a) आर्थिक परिणाम :-
  - i) मानव शक्ति का अप्रयोग :- जिस सीमा तक देश में लोग वैराजगार करते हैं, उस सीमा तक देश में मानवीय साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता है।
  - ii) उत्पादन की कमी :- जिस सीमा तक मानव शक्ति प्रयोग नहीं हो पाता है, उस सीमा तक उत्पादन की हानि होती है।
  - iii) पूंजी निर्माण में गिरावट :- वैराजगार के कारण निवेश पूंजी में वृद्धि के लिए कुछ भी आर्थिक का प्रयत्न नहीं करते हैं। पूंजी निर्माण की दर को क्षीण होती है।
  - iv) कम उत्पादकता :- निम्न उत्पादकता का अर्थ है कि विकास के लिए उत्पादन से कम आर्थिक की प्राप्ति।

- \* सामाजिक परिणाम :-
  - i) जीवन की निम्न गुणवत्ता :- वैराजगारी जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती है।

b) अत्यधिक असमानता - वैरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी अधिक होगी।

c) सामाजिक अक्षान्ति - अक्षान्ति और आतंकवाद का कोई अन्य तर्क से प्रेरणा मिलती है परंतु वैरोजगारी एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के रूप में अनदेखी नहीं की जा सकती है।

d) वर्ग संघर्ष - वैरोजगारी को हम समाज में ह कर नहीं देते हैं। इसके परिणामस्वरूप को संघर्ष कम होता है। जो सामाजिक अक्षान्ति को और भी बढ़ावा देती है।

वैरोजगारी इत करने के उपाय

- i) उत्पादन में बढ़ोत्तरी
- ii) पूंजी निर्माण की तेजी देना
- iii) छोटे और ग्रामीण उद्योगों का प्रोत्साहन
- iv) वैरोजगार में लगे लोगों को अधिक सहायता
- v) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन
- vi) औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन
- vii) जनसंख्या पर नियंत्रण

\* वैरोजगारी इत करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाये कार्यक्रम:

1) जवाहर रोजगार योजना - 28 April, 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण मूविलेन रोजगार गारंटी कानून कार्यक्रम को मिलाकर इस योजना के अर्धन कर दिया गया है।

2) रोजगार आश्वासन योजना - 2 Oct, 1993 को 1,772 पिछड़े विकास खण्डों में आरंभ की गई थी। ये विकास खण्ड सूखा ग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में थे। बाद में इस रोजगार कार्यक्रम का विस्तार सभी 5,448 ग्रामीण विकास खण्डों में किया गया।

(c) स्वम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना : — जवाहर ग्राम समूह योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर 2001 को संयुक्त ग्रामीण योजना को गठन किया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकारों इस योजना को लागू करने का उद्देश्य 87.5:12.5 में बहन करती है। इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार को व्यवस्था करना सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना को निर्माण करना इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू करने का प्रावधान है।

(d) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना : — इस योजना को आरंभ 1 December 1997 को किया गया। इस योजना को मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्परोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इस योजना को 75% खर्च केन्द्र सरकार तथा 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

(e) पंच प्रकल्प रोजगार गारन्टी योजना इस योजना को प्रारंभ 2002-03 में की गई। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन को रोजगार उपलब्ध कराना है।

(f) प्रधानमंत्री रोजगार योजना : — इस योजना को आरंभ 18 Nov 1995 को किया गया। इस योजना को द्वारा 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य विविध सहायता प्रदान करना है।

(9) महिला स्वयं सहा योजना :- इस योजना की शुरुआत 12 July 1995 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक समानता कलना है।

(10) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना -> इस योजना को 2 Feb 2006 में लागू किया गया। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारंटी देने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वयस्क व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करना है।

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विषय वर्ष 15 August 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का गठन किया गया है।

- मुख्य विभागों द्वारा परियोजना को चलाते हुए प्रोब्लम प्रोफाइल प्रदान की जाएगी।
- सूचना प्रार प्रोब्लम का निर्माण इसके अंतर्गत दो से तीन सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम को द्वारा प्रशिक्षण एवं निपटण सहयोग लाभार्थियों को आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक टूल्किंग, बैचर्स एवं फावर्स पैकेज सहायता को प्रवधान किया गया है।
- उद्यमिता हेतु कोलेटर (बैंचर) सुझा मुक्त त्रेण प्राप्त में सहायता को लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना से जोड़ना।
- 10 लाख रु से अधिक की उत्पादन परियोजनाओं तथा 5 लाख रु से अधिक के व्यापार।
- समग्र विकास हेतु समाज को वंचित वर्गों को लिए ज्यादा सहायता।

